यूपी की चीनी मिलों ने मांगी मदद

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 31 मई

बकाया बढ़कर 5000 करोड़ रुपये

- चीनी मिलों के संगठन ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लिखा खत
- चीनी पर प्रवेश शुल्क खत्म किए जाने, शीरे को नियंत्रण मुक्त किए जाने की मांग
- केंद्र सरकार से चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाने की भी मांग

कर्ज के बोझ तले दबी उत्तर प्रदेश की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों ने अखिलेश यादव सरकार से तत्काल राहत दिए जाने की मांग की है। राज्य की मिलों पर गन्ने का बकाया बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। मिलों ने तत्काल राहत के तौर पर चीनी पर प्रवेश शुल्क खत्म किए जाने और शीरे को पूरी तरह नियंत्रण से मुक्त किए जाने की मांग की है।

इसके साथ ही मिलों ने गन्ना समिति कमीशन 5.10 रुपये प्रति क्विंटल में 3 रुपये प्रति क्विंटल की कमी किए जाने और गन्ने के दाम पर 15 रुपये प्रति क्विंटल नकद सब्सिडी या 5 साल के लिए ब्याज रहित कर्ज दिए जाने की मांग की है।

यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन (यूपीएसएमए) के अध्यक्ष सीबी पटौदिया ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में लिखा है, ' चीनी फैक्टरियों की इस साल की वित्तीय हालत के बारे में राज्य सरकार अच्छी तरह से वाकिफ है।' उन्होंने सहकारी चीनी मिलों को 400-500 करोड़ रुपये के प्रस्तावित राहत पैकेज का भी हवाला दिया है, जिससे सहकारी मिलों सहारा मिल सके, जो खस्ता वित्तीय हालत से जूझ रही हैं। किसान जागृति मंच के अध्यक्ष सुधीर पंवार ने केंद्र सरकार से चीनी मिलों को संकट से उबारने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में एकमात्र चीनी उद्योग ही है, जिससे किसानों को सीधे नकदी मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के हितों को देखते हुए नीतिगत फैसला करना चाहिए। 2012-13 पेराई सत्र में उत्तर प्रदेश की 121 मिलों ने करीब 74.7 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, जो पिछले साल हुए 69.7 लाख टन उत्पादन की तुलना में 7 प्रतिशत ज्यादा है। चालू सत्र में 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा गन्ने का बकाया है।

पंजाब में बढ़े गन्ने के दाम

पंजाब सरकार ने 2013-14 के पेराई सत्र के लिए आज गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) में 40 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। पंजाब ने अब उन्नत किस्म के लिए नया एसएपी 290 रुपये प्रति क्विंटल, मध्यम किस्म के लिए 280 रुपये प्रति क्विंटल और देर से आने वाली किस्मों के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में गन्ना नियंत्रण बोर्ड की एक बैठक में यह फैसला किया गया। वर्ष 2012-13 के गन्ना पेराई सत्र में एसएपी की दरें उन्नत, मध्यम और देर से आने वाली किस्मों के लिए क्रमश: 250 रुपये, 240 रुपये और 235 रुपये प्रति क्विंटल है। गन्ने की दरों में यह वृद्धि इस बात को ध्यान में रखकर की गई है कि अधिक पानी की खपत करने वाली धान की फसल के रकबे को कम किया जाए और गन्ने और कपास के खेती के रकबे में वृद्धि की जाए।

Hindi-Business Standard
1/6/13